ISSN: 0973-0583

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन का विश्लेषण: भारत के शिक्षा परिदृश्य को बदलने में चुनौतियाँ और अवसर

डॉ० धर्मेन्द्र कुमार

प्राचार्य, आर. एल. महतो इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन

रामपुर जलालपुर, दलसिंह सराय, समस्तीपुर, बिहार

'kks/k lkj

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करना है ताकि इसे 21वीं सदी की बदलती मांगों के अनुकूल बनाया जा सके। यह अध्याय बताता है कि एन.ई.पी. 2020 को कैसे लागू किया जा रहा है, साथ ही भारत की शिक्षा प्रणाली में बदलाव के कारण सामने आगे संभावनाओं और समस्याओं पर प्रकाश डालता है। अध्ययन के लिए प्राथमिक डेटा स्रोत द्वितीयक डेटा है। परिणाम एन.ई.पी. 2020 के कार्यान्वयन की जटिलताओं पर प्रकाश डालते हैं, जो भारत में शिक्षा सुधार के बारे में निरंतर बातचीत में योगदान देता है। पहचाने गए मुद्दों से निपटने के लिए सुझाव दिए गए हैं, जिसमें एक सहकारी और लचीली रणनीति के विकास पर जोर दिया गया है जो विभिन्न क्षेत्रों और आबादी की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। यह अध्याय शैक्षिक परिवर्तन के बदलते और गतिशील क्षेत्र में भारत की सहायता करना चाहता है।

'kCn dqath % jk"Vªh; f'k{kk uhfr ¼,u-Ã-ih- 2020½] f'k{kk ç.kkyh] ifjorZudkjh f'k{kk

परिचय:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 ने भारतीय शैक्षणिक माहौल में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। तीस साल के अंतराल के बाद अनावरण की गई इस ऐतिहासिक रणनीति का उद्देश्य देश में शिक्षा को देखने, व्यवस्थित करने और प्रदान करने के तरीके को मौलिक रूप से बदलना है। इस क्रांतिकारी यात्रा के करीब होने के साथ, यह महत्वपूर्ण है कि हम एन.ई.पी. 2020 को क्रियान्वित करने की जटिल प्रक्रिया की जाँच करें, इस आकार की परियोजना के साथ आने वाली कठिनाइयों के साथ-साथ इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले असंख्य अवसरों को स्वीकार करें।

भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलने के लक्ष्य के साथ, एन.ई.पी. 2020 एक दूरदर्शी घोषणापत्र है जो छात्रों को आलोचनात्मक, समग्र और वैश्विक रूप से विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करता है (अख्तर, 2021)। यह नीति, जो माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा दोनों को कवर करती है, संरचनात्मक परिवर्तन लाती है, अनुकूलनशीलता को प्राथमिकता देती है और एक शैक्षिक ढाँचा विकसित करने के लक्ष्य के साथ विविधता को प्रोत्साहित करती है जो न केवल इकीसवीं सदी की बदलती माँगों के प्रति संवेदनशील हो बल्कि भारतीय संस्कृति और नैतिकता में भी गहराई से समाहित हो (कुमार, 2021)।

हालांकि, इस व्यापक नीति का प्रभावी क्रियान्वयन अपनी चुनौतियों के बिना नहीं हैं। यह अध्याय एन.ई.पी. 2020 के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली कठिनाइयों की गहन जाँच शुरू करता है। नीति संचार से लेकर वास्तविक कार्यान्वयन तक की समस्याओं को तोड़ता है। साथ ही, हम उन संभावनाओं पर भी गौर करते हैं जो इन कठिनाइयों से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई हैं, भारत के शैक्षिक वातावरण में क्रांति लाने की योजना तैयार करते हैं। यह अध्याय हमें शैक्षिक सुधार के जटिल पहलुओं की यात्रा पर ले जाता है, नीति के लक्ष्यों और इसके वास्तविक कार्यान्वयन के बीच के नाजुक संबंधों पर प्रकाश डालता है। शिक्षकों से लेकर अभिभावकों, नीति निर्माताओं से लेकर छात्रों तक सभी हितधारकों के सामने आने वाली बाधाओं के विश्लेषण के माध्यम से, हमारा लक्ष्य उन मुद्दों की व्यापक समझ विकसित करना है, जिन्हें एन.ई.पी. 2020 के महान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दूर करने की आवश्यकता है। साथ ही, हम उन अवसरों का पता लगाते हैं जो इन कठिनाइयों की सतह

के नीचे छिपे हैं, यह महसूस करते हुए कि वे रचनात्मकता, टीम वर्क और एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली के विकास के लिए उत्तेजक के रूप में काम कर सकते हैं जो विशेष रूप से भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण के अनुकूल हो और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो।

शिक्षकों, नीति निर्माताओं, शिक्षा विदों और भारत में शिक्षा के भविष्य में रुचि रखने वाले अन्य सभी लोगों के लिए एक उपयोगी संसाधन होगा क्योंकि हम इस बौद्धिक यात्रा पर निकल रहे हैं। हमारा लक्ष्य एन.ई.पी. 2020 के कार्यान्वयन की आलोचनात्मक जाँच करके शिक्षा में सुधार पर वर्तमान बातचीत में योगदान देना है। हम आशा करते हैं कि हम ऐसी अंर्तदृष्टि प्रदान करके ऐसा कर सकेंगे जो रणनीतिक निर्णय लेने में मार्गदर्शन कर सके। नवीन प्रथाओं को प्रोत्साहित कर सके तथा अंतत: भारत में पुन: डिजाइन किए गए शैक्षिक वातावरण का निर्माण कर सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अवलोकन

भारत में शिक्षा के भविष्य के लक्ष्य और मार्ग को व्यापक और परिवर्तनकारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में रेखांकित किया गया है। शिक्षा पर पूर्व राष्ट्रीय नीति, जिसे 1986 में विकसित किया गया था और 1992 में संशोधित किया गया था, को एन.ई.पी. 2020 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

एन.ई.पी. 2020 की मुख्य विशेषताएँ:

1. समग्र और बहुविषयक शिक्षा: भारत में शिक्षा के भविष्य के लिए दृष्टिकोण और मार्ग को रेखांकित करते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक व्यापक और परिवर्तनकारी दस्तावेज़ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे 29 जुलाई, 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, ने पिछली नीति को प्रतिस्थापित किया है, जिसे 1986 में बनाया गया था और 1992 में बदल दिया गया था।

2. लचीलापन और विकल्प: एन.ई.पी. 2020 द्वारा विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर विषय और पाठ्यक्रम चयन लचीलापन पेश किया जा रहा है। छात्रों के लिए विभिन्न धाराओं से पाठ्यक्रम चुनने की क्षमता शिक्षा के लिए अधिक व्यक्तिगत और कौशल-केंद्रित दृष्टिकोण की अनुमति देती है। उच्च शिक्षा के लिए, एक क्रेडिट-आधारित प्रणाली का सुझाव दिया गया है, जो छात्रों के लिए विभिन्न स्कूलों और पाठ्यक्रमों के बीच स्थानांतरण को आसान बना देगा।

3. भाषा नीति: रणनीति बहुभाषावाद को बढ़ावा देती है, साथ ही कम से कम ग्रेड 5 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षण की प्राथमिक भाषा के रूप में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका लक्ष्य भाषाई विविधता और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देते हुए प्रभावी शिक्षण प्रदान करना है।

4. मूल्यांकन में सुधार: मूल्यांकन प्रक्रियाओं को रटने की जगह योग्यता-आधारित सीखने और रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देने के साथ पुनर्गठित किया गया है (बत्रा, 2020)। बोर्ड परीक्षाओं को फिर से डिजाइन करने का उद्देश्य ज्ञान के अनुप्रयोग को मापना, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और मूलभूत सिद्धांतों का मूल्यांकन करना है।

5. शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास: एन.ई.पी. 2020 में शिक्षकों के लिए निरंतर व्यावसायिक विकास को अत्यधिक महत्व दिया गया है, जिसमें शैक्षणिक प्रशिक्षण, रचनात्मक शिक्षण तकनीकों और कक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षक विकास को निर्देशित करने के लिए, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी) के रूप में जाना जाने वाला एक नया ढांचा सुझाया जा रहा है।

6. प्रौद्योगिकी एकीकरण: एन.ई.पी. 2020 कक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देता है। इसका उद्देश्य डिजिटल सामग्री, ऑनलाइन संसाधनों और अनुकूली शिक्षण रणनीतियों के अनुप्रयोग द्वारा सीखने में सुधार करना है। सर्वोत्तम प्रथाओं और विचारों को साझा करने में आसानी के लिए, नीति राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF) की स्थापना को प्रोत्साहित करती है।

7. उच्च शिक्षा सुधार: अधिक स्वायत्तता, शैक्षणिक लचीलापन और शोध-उन्मुख शिक्षा का समर्थन करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों का पुनर्गठन एन.ई.पी. 2020 के लक्ष्यों में से एक है। यह सुझाव दिया गया है कि अंत: विषय शिक्षा का समर्थन और वित्तपोषण करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना की जाए।

8. समावेशी शिक्षा: नीति समावेशिता पर जोर देती है, जिसका उद्देश्य विकलांगों सहित सभी छात्रों के लिए समान अवसर प्रदान करना है। वंचित क्षेत्रों और समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र प्रस्तावित है।

9. वैश्विक जुड़ावः अधिक स्वायत्तता, शैक्षणिक लचीलापन और शोध-उन्मुख शिक्षा का समर्थन करने के लिए, एन.ई.पी. 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव करता है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को अनुसंधान परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने और वित्तपोषित करने के साधन के रूप में सुझाया गया है और बहु-विषयक शिक्षा का समर्थन किया गया है। पारंपरिक तरीकों से एक बड़ा विचलन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जो एक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना चाहता है जो अधिक अनुकूलनीय, समावेशी शिक्षा की बदलती मांगों के अनुरूप हो। इस पहल के सफल कार्यान्वयन के लिए भारत के शैक्षिक परिदृश्य में वांछित परिवर्तन लाने हेतु विभिन्न हितधारकों के सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता होगी।

एन.ई.पी. 2020 के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

हालाँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एन.ई.पी. 2020 के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, फिर भी एन.ई.पी. बाधाएँ हैं जिन पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। (मार्ने और देशमुख, 2022)। नीति के लक्ष्यों के प्रभावी कार्यान्वयन की गारंटी के लिए इन बाधाओं से निपटना अनिवार्य है। एन.ई.पी. 2020 के कार्यान्वयन में ये मुख्य बाधाएँ हैं।

1. संसाधन आवंटन और वित्त पोषणः एन.ई.पी. 2020 को लागू करने के लिए बुनियादी ढाँचे को आधुनिक बनाने, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने, पाठ्यक्रम बनाने और प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है। (अख्तर, 2021)। हालाँकि, परस्पर विरोधी उद्देश्यों और बजटीय प्रतिबंधों के कारण इन प्रयासों के लिए पर्याप्त नकदी आवंटित करना मुश्किल है।

2. शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माणः आधुनिक शैक्षणिक विधियों और पद्धतियों के अनुरूप होने के लिए, नीति व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। फिर भी, यह देश भर में कई शिक्षकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण सत्रों की योजना बनाने के लिए एक तार्किक समस्या प्रस्तुत करता है (ऐथल और ऐथल, 2020)। एक और चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि ये प्रशिक्षण सत्र कुशल और उच्च गुणवत्ता वाले हों।

3. पाठ्यक्रम में बदलाव और सामग्री विकासः बहु-विषयक विधियों और एक नये पाठ्यचर्या संरचना को लागू करने के लिए पाठ्यक्रम सामग्री को बदलने की आवश्यकता है। यह एक कठिन कार्य है जिसमें एकरूपता और गुणवत्ता बनाए रखते हुए इन सामग्रियों को बड़े पैमाने पर डिजाइन और तैनात करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना और समन्वय की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक शिक्षा में स्पष्ट और मौन जानकारी का एकीकरण एक अधिक व्यापक सीखने का अनुभव बनाने के लिए जो बदलाव को बढ़ावा देता है। तीन संस्थाओं द्वारा उत्पन्न ज्ञान की मात्र में एक उल्लेखनीय असमानता मौजूद है: व्यावसायिक फर्म, शिक्षार्थी और बी-स्कूल। अंतर को पाटने के लिए, उद्योग के तरीकों से आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान को आसानी से अकादमिक प्रशिक्षण में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सीखने के अंतर को कम करने के लिए व्यावसायिक उद्यमों को बिना किसी हिचकिचाहट के बी-स्कूलों के साथ बातचीत करनी चाहिए (कुमार और पदशेटी, 2021)।

4. भाषा कार्यान्वयन चुनौतियाँः ग्रेड 5 तक, नीति किसी की मूल भाषा या स्थानीय भाषा में निर्देश का समर्थन करती है। हालाँकि, देश के विषम भाषाई वातावरण (मार्ने और देशमुख, 2022) के कारण पूरे भारत में इस सलाह को लगातार लागू करना मुश्किल होगा। एक और मुद्दा स्थानीय भाषाओं में उपयुक्त शिक्षण संसाधन बनाना है।

5. परिवर्तन का प्रतिरोधः शिक्षा में सुधारों को अक्सर संस्थानों और संस्कृतियों से परिवर्तन का प्रतिरोध झेलना पड़ता है। नए शैक्षणिक दृष्टिकोणों को स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, जो अधिक पारंपरिक तरीकों के आदी हैं, जिससे पूरे शैक्षणिक तंत्र में नीति को लगातार लागू करना मुश्किल हो जाता है।

6. प्रौद्योगिकी एकीकरण और पहुँचः यद्यपि एन.ई.पी. 2020 कक्षा में प्रौद्योगिकी एकीकरण को बढ़ावा देता है, लेकिन शहरी और ग्रामीण दोनों स्थानों में प्रौद्योगिकी तक समान पहुँच प्रदान करना मुश्किल हो सकता है (ऐथल और ऐथल, 2020)। कुशल ई-लर्निंग और डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा बनाना तार्किक और वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

7. मूल्यांकन और परीक्षा सुधारः योग्यता-आधारित शिक्षण और आलोचनात्मक सोच (मार्ने और देशमुख, 2022) का समर्थन करने के लिए परीक्षाओं और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को फिर से डिज़ाइन करना एक कठिन काम है। कार्यान्वयन की बाधाओं में नए मूल्यांकन ढाँचे बनाना, मूल्यांकनकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना और परीक्षाओं की कथित गंभीरता के बारे में मुद्दों को हल करना शामिल है।

8. समावेशिता और पहुँच: समावेशी पाठ्यचर्या सामग्री विकसित करना, सुलभ बुनियादी ढाँचा बनाना और छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को तैयार करना, विकलांगों सहित सभी के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने की राह में बाधाएँ हैं।

9. निगरानी और मूल्यांकन: संघीय और राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, अभिभावकों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों को एन.ई.पी. 2020 को सफलपूर्वक लागू करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अलग-अलग प्राथमिकताएँ और हित किसी समझौते पर पहुँचना और प्रभावी ढंग से सहयोग करना मुश्किल बना सकते हैं। इन मुद्दों को हल करने के लिए विधायकों, शिक्षकों, प्रशासकों और समुदाय को शामिल करने वाली एक व्यवस्थित और सहकारी रणनीति की आवश्यकता है। (ऐथल और ऐथल, 2020)। इसके अतिरिक्त, इसमें कार्यान्वयन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए चल रहे फीडबैक चैनल और नई चुनौतियों से निपटने के लिए अनुकूली योजना शामिल है।

एन.ई.पी. 2020 के नये परिवर्तन के अवसर

यदि उचित तरीके से लाभ उठाया जाए, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ऐसी अनेक पहलों की पेशकश करती है, जिनमें भारत के शैक्षिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता है। इन अवसरों के परिणामस्वरूप शिक्षा प्रदान करने, उस तक पहुँचने और उसे समझने का तरीका सभी में सुधार हो सकता है। एन.ई.पी. 2020 के ढांचे के भीतर परिवर्तन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं:

1. समग्र विकास पर जोर: समग्र विकास पर जोर छात्रों के शैक्षणिक विकास के अलावा उनके सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। सिद्धांतों, अनुभव सीखने और जीवन कौशलों को मिलाकर लोगों को अच्छी तरह से विकसित होने में मदद मिल सकती है, जो वास्तविक दुनिया में आने वाली बाधाओं को संभालने में सक्षम हैं।

2. बहु-विषयक शिक्षा: समग्र विकास पर जोर देने से सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक स्तर पर विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति रखना संभव हो जाता है। जीवन कौशल, मूल्यों और अनुभवात्मक शिक्षा को मिलाकर अच्छी तरह से विकसित लोग बनाए जा सकते हैं जो वास्तविक दुनिया में आने वाली बाधाओं को संभाल सकते हैं।

3. शिक्षा में लचीलापन: विषय और पाठ्यक्रम चुनने की स्वतंत्रता के आगमन के साथ, छात्र अब अपने जुनून और रुचियों का पालन कर सकते हैं। इस लचीलेपन के कारण, सीखने के मार्ग प्रत्येक छात्र की रुचियों और शक्तियों के अनुरूप बनाए जा सकते हैं।

4. भाषा विविधता और सांस्कृतिक संरक्षण: ग्रेड 5 तक शिक्षण की प्राथमिक भाषा के रूप में मातृभाषाओं या क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देना भाषाई विविधता बनाए रखने और सांस्कृतिक संबंध बनाने का अवसर प्रदान करता है। यह विधि बच्चों को पहचान की भावना विकसित करने और उनकी वैचारिक समझ को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।

5. उन्नत शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी एकीकरण: प्रौद्योगिकी एकीकरण पर एन.ई.पी. 2020 का ध्यान अत्याधुनिक शिक्षण रणनीतियों, ऑनलाइन शिक्षण वातावरण और डिजिटल संसाधनों के लिए अवसर पैदा करता है। पहुँच में सुधार के अलावा, यह इंटरैक्टिव सीखने के अवसर प्रदान करने और बच्चों को डिजिटल युग के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है।

6. शिक्षकों के लिए सतत व्यावसायिक विकास: निरंतर व्यावसायिक विकास पर जोर शिक्षकों को वर्तमान शैक्षणिक ज्ञान, शिक्षण रणनीतियों और तकनीकी एकीकरण से लैस करने का एक मौका है। प्रभावी एन.ई.पी. कार्यान्वयन और उच्च-गुणवत्तापूर्ण निर्देश मुख्य रूप से आवश्यक प्रशिक्षण वाले शिक्षकों पर निर्भर हैं।

7. कौशल मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन सुधार: रटने की आदत को त्यागने और व्यावहारिक कौशल, आलोचनात्मक सोच और ज्ञान के अनुप्रयोग का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित करने का मौका योग्यता-आधारित मूल्यांकन की ओर बदलाव से आता है। इसके परिणामस्वरूप एक मूल्यांकन प्रक्रिया हो सकती है जो अधिक प्रासंगिक और सार्थक है।

8. वैश्विक सहयोग और अनुसंधान: एन.ई.पी. 2020 में भारत को शिक्षा के लिए एक विश्वव्यापी केंद्र के रूप में देखा गया है जो विदेशी छात्रों को आकर्षित करेगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा। यह सर्वोत्तम अभ्यास विनिमय, क्रॉस-कल्चरल लर्निंग और अंतर्राष्ट्रीय शोध परियोजनाओं में भागीदारी का अवसर प्रदान करता है (कुमार, ए. 2021)।

9. सामुदायिक जुड़ाव और भागीदारी: शैक्षणिक प्रक्रिया में समुदायों को शामिल करने की एन.ई.पी. की सिफारिश सक्रिय भगीदारी और समूह निर्णय लेने को बढ़ावा देती है। शैक्षिक प्राणाली में, इस सामुदायिक भागीदारी के परिणामस्वरूप जवाबदेही और स्वामित्व की भावना पैदा हो सकती है।

10. समावेशी शिक्षा अभ्यास: नीति में समावेशी शिक्षा पर जोर विकलांग छात्रों के लिए एक स्वागत योग्य और उत्साहजनक शिक्षण वातावरण स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है (गोलवदा, 2020)। एक शैक्षिक वातावरण जो अधिक विविधतापूर्ण और समान है, समावेशी दृष्टिकोण से लाभान्वित हो सकता है।

11. उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार: राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन बनाकर, एन.ई.पी. 2020 उच्च शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देता है (कुमार, ए 2021)। यह भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की क्षमता और प्रयोग को बेहतर बनाने का अवसर प्रदान करता है। इन अवसरों का लाभ उठाकर, निर्णयकर्ता, शिक्षक और इच्छुक पक्ष शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए सहयोग कर सकते हैं, इसे 21वीं सदी की मांगों के अनुरूप ला सकते हैं और छात्रों के समग्र विकास का समर्थन कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

यह अध्याय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन की गहन जाँच प्रदान करता है, जो इस क्रांतिकारी यात्रा के साथ आने वाली संभावनाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। यह इस बात पर जोर देता है कि संसाधनों के वितरण और शिक्षक तैयारी से लेकर क्षेत्रीय और सांस्कृतिक भिन्नताओं तक, कई अलग-अलग समस्याओं की परिष्कृत समझ होना कितना महत्वपूर्ण है। इन कठिनाइयों के भीतर मौजूद अवसरों की अधिकता पर भी जोर दिया गया है, जिसमें रचनात्मक शैक्षिक दृष्टिकोण, सर्वव्यापी विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए, राजनेताओं, शिक्षकों और हितधारकों को अनुकूलनीय समाधान विकसित करने और निरंतर सुधार संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। संसाधनों के वितरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शिक्षक तैयारी को वित्त पोषित किया जाना चाहिए, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:

1. ऐथल, पी. एस., और ऐथल, एस. (2020). इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज ऑफ हायर एजुकेशन, पार्ट ऑफ़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ऑफ इंडिया टुवर्ड्स अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एण्ड सोशल साइंसेज (आईजेएमटीएस), 5(2), 283-325।
2. अख़्तर, एस. (2021). न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑफ इंडिया: अ थ्योरेटिकल एनालिसिस। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिसर्च, 9(3), 302-306।
3. बत्रा, पी. (2020). एनईपी 2020: अंडरमाइनिग द कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन एजेंडा?
4. गोलवदा, आर. (2020). एनईपी 2020: अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन।
5. कुमार, ए. (2021). न्यू एजुकेशन पॉलिसी (एन.ई.पी) 2020: अ रोडमैप फॉर इंडिया 2.0। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फोलोरिडा एम सेंटर पब्लिशिंग, 3(2021), 36।
6. कुमार, के., प्रकाश, ए., और लसह, के. (2021). हाउ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कैन बी अ लोडस्टार टू ट्रांसफर्म "यूचर जेनेरेशन इन इंडिया। जर्नल ऑफ़ पब्लिक अफेयर्स, 21(3), 2500 ।
7. कुमार, एस. और पाडाशेटी, एस. (2021). को-क्रिएशन ऑफ नॉलेज बिटवीन बिजनेस स्कूल्स, बिजनेस फर्म्स, और लर्नर्स। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिसेज़, 9, 26-31।
8. मर्ने, जी. एस., और देशमुख, एन. एस. (2022). नेशनल एजुकेशन पॉलिसी-2020: इशूज एंड चैलेंजेस। जर्नल ऑफ द ओरिएंटल इंस्टिटयूट ।
9. मेनन, एस. (2020). एनईपी 2020: सम सचिग क्वेशचन्स।
10. पंडित्राओ, एम. एम., और पंडित्राओ, एम. एम. (2020). नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020: व्हाट इज इन इट फॉर अ स्टूडेंट, अ पेरेंट, अ टीचर, और अस, ऐस अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन/यूनिवर्सिटी? अदेश यूनिवसिटी जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च, 2(2), 70-79।

❖❖❖